आधुनिक सुविधाओं से गौवंश को त्वरित व प्रभावी उपचार मिलेगा- भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री ने देवनारायण गौशाला में आधुनिक गौ-चिकित्सालय का उद्घाटन किया

शाहपुरा, भीलवाड़ा,जयपुर, 6 सितम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गौमाता का सनातन संस्कृति में हमेशा से सर्वोच्च स्थान रहा है। गौ-वंश की अपार महिमा के चलते ही छोटे से लेकर बड़े अनुष्ठानों में गाय को पूजा जाता है। गाय को आर्थिक समृद्धि, कृषि और आयुर्वेद का आधार एवं पर्यावरण संरक्षक माना गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी प्रदेश में गौवंश संरक्षण और गोपालकों की सहायता के लिए निरंतर अहम निर्णय ले रही है, जिससे गौवंश का संरक्षण और संवर्द्धन सुनिश्चित हो सके।

शर्मा शुक्रवार को शाहपुरा के कोटड़ी में श्री सुरभि गौ-चिकित्सालय, गौ गृह एवं आई.टी.आई. भवन के उद्घाटन और सामुदायिक भवन एवं किसान प्रशिक्षण सभागार के विस्तारीकरण के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की देवनारायण गौशाला में आधुनिक गौ चिकित्सालय की कमी के कारण श्री सुरभि चिकित्सालय का शुभारंभ किया गया है। इस गौ चिकित्सालय में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होने से अब गौवंश का उपचार त्वरित और प्रभावी रूप से हो सकेगा। उन्होंने दानदाताओं-भामाशाहों का इस चिकित्सालय में व्यापक प्रबंधन के लिए आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से गोपालकों के लिए एक लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण, पंजीकृत गौशालाओं के अनुदान में 10 प्रतिशत वृद्धि,100 गौशालाओं को रियायती दरों पर गौ काष्ठ मशीन उपलब्ध करवाने सहित विभिन्न कार्य गौमाता के संवर्धन के लिए किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में शाहपुरा जिले के विकास का पूरा ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्थानों पर सड़क निर्माण एवं चौड़ाईकरण कार्य करवाए जाएंगे। औद्योगिक विकास के लिए यहां पीपलूंद में औद्योगिक क्षेत्र तथा पंडेर में औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। साथ ही, जहाजपुर में कन्या महाविद्यालय, कोटड़ी में नवीन महाविद्यालय, जहाजपुर में जनजाति छात्रावास और सरसिया में जनजाति बालिका छात्रावास खोलने जैसे अहम निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों एवं चिकित्सालयों का क्रमोन्नयन भी किया जा रहा है। बनेड़ा में खेल स्टेडियम, शाहपुरा में खेल अकादमी और काले हिरणों के संरक्षण के लिए शाहपुरा के आसोप क्षेत्र को आखेट निषिद्ध एवं कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र भी घोषित किया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शाहपुरा स्थित कोटड़ी में श्री सुरभि गौ-चिकित्सालय का उद्घाटन करने के बाद गौ-वंश की पूजा भी की। उनके साथ गौपालन मंत्री जोराराम कुमावत भी मौजूद थे।

- **मुख्यमंत्री ने कहा, गाय को आर्थिक समृद्धि, कृषि व आयुर्वेद का आधार व पर्यावरण संरक्षक माना गया है।**
- **इस अवसर पर मु.मंत्री ने बताया कि शाहपुरा जिले में औद्योगिक क्षेत्र तथा महाविद्यालय, जनजाति बालिका छात्रावास खोले जायेंगे।**

गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि सनातन संस्कृति में गौ माता की पूजा को महत्वपूर्ण बताया गया है तथा हमारे जीवन में भी गौवंश बहुत उपयोगी है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने देवनारायण गौशाला में गौमाता का पूजन किया। कार्यक्रम में सांसद राजेन्द्र गहलोत, दामोदर अग्रवाल, विधायक गोपीचंद मीणा, अशोक कोठारी, उदयलाल भड़ाना, लादूलाल पीतलिया, गोपाल लाल शर्मा, संत राधाकृष्ण महाराज, आर.एस.एस. के क्षेत्र प्रचारक निंबाराम सहित बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोटड़ी के चारभुजा नाथ मंदिर परिसर में भगवान चारभुजा नाथ और सर्वेश्वर महादेव के दर्शन किए तथा पूजा अर्चना की।

बी.जे.डी. सांसद सुजीत कुमार भाजपा में शामिल

नयी दिल्ली, 6 सितंबर (वार्ता) बीजू जनता दल (बीजद)के राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दामन थाम लिया। भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान,ओडिशा के प्रभारी विजय पाल तोमर, वरिष्ठ सांसद भर्तृहरि महताब, भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी की उपस्थिति में सुजीत कुमार ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। ओडिशा के कालाहांडी के रहने वाले सुजीत कुमार ने इससे पहले राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। राजनीति में आने से पहले वह अमेरिका के हॉर्वर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ समेत कई अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में कार्य कर चुके हैं।

- **बी.जे.डी. के सांसद सुजीत कुमार को राज्य में बीजू जनता दल का बड़ा चेहरा माना जाता था तथा वे पूर्व मु.मंत्री नवीन पटनायक के भी काफी भरोसेमंद कहे जाते थे।**

हरियाणा में कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन की वार्ता टूटने की कगार पर

कांग्रेस ने हरियाणा में 90 में से 66 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिये हैं तथा आप ने भी राज्य में 50 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने की तैयारी शुरु कर दी है

नई दिल्ली, 6 सितंबर। हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन शुरू हो चुके हैं। इस बीच कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की शुक्रवार शाम नई दिल्ली में बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे लेकिन राहुल गांधी के इस बैठक में शामिल होने पर सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि उन्हें अमेरिका की यात्रा पर निकलना है। कांग्रेस ने देर रात हरियाणा के 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी तथा पार्टी ने 66 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए हैं लेकिन उसका ऐलान अभी तक नहीं किया गया है।

वैसे पार्टी ने जिन 66 नामों को तय किया है, उन्हें निजी तौर पर बताया जा रहा है कि चुनाव की तैयारी करें। पार्टी सभी 66 नामों का ऐलान दो वजहों से नहीं कर रही है। पहली कि पार्टी को इस बात की आशंका है कि नामों की घोषणा होने से असंतुष्ट नेता बगावत या भितरघात ना कर दें और दूसरी वजह यह है कि अभी आप के साथ सीट बंटवारे पर अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। राहुल गांधी की हरियाणा में आप पार्टी से चुनावी गठबंधन की रणनीति पूरी तरह से परवान नहीं चढ़ पाई है और कहा जा रहा है कि इस गठबंधन की बातचीत अब टूटने की कगार पर पहुँच चुकी है।

वैसे सूत्रों के मुताबिक हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत तमाम वरिष्ठ कांग्रेसी आप के साथ गठबंधन को तैयार हो चुके हैं और आप को पांच सीटें देने को राजी हैं लेकिन आप 10 से कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि हुड्डा आप पार्टी को 5 से ज्यादा सीटें किसी सूरत में नहीं देना चाहते। उन्होंने आशंका जताई है कि ज्यादा सीटें आपा पार्टी को देने के कारण पार्टी में असंतुष्ट नेताओं की नाराजगी और बढ़ जायेगी। आम आदमी पार्टी फिलहाल वेट एंड वॉच की नीति अपना रही है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने का इंतजार भी हो रहा है।

- **मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कांग्रेस आप पार्टी को पांच सीटें देना चाहती थी, जबकि, आप पार्टी कम से कम 10 सीटों की मांग कर रही है।**
- **दूसरी ओर इस गठबंधन की वजह से वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेन्द्र सिंह हुड्डा भी नाराज थे, उनका कहना था कि इस गठबंधन की वजह से पार्टी में असंतुष्ट नेताओं की नाराज़गी और बढ़ जायेगी।**

भारतीय एथलीट प्रवीण कुमार ने शुक्रवार को पेरिस पैरालिंपिक 2024 खेलों में पुरुषों की लॉन्ग जम्प टी-64 के फाइनल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया और एशिया का सर्वश्रेष्ठ लॉन्ग जम्प का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। इस पदक के साथ ही पैरालिंपिक खेलों में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है और भारत पैरालिंपिक खेलों की पदक सूची में 14वें पायदान पर पहुँच गया है।

'टायर फटने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

व लापरवाही से बस चलाने से हुई है। उसकी लापरवाही के कारण ही बस ने डिवाइडर से टकराकर पलटी खाई। इस दुर्घटना को एक्ट ऑफ गॉड की श्रेणी में मानकर मुआवज़े से इन्कार नहीं किया जा सकता। इसलिए बीमा कंपनी अपने क्लेम देने की जवाबदेही से बच नहीं सकती। अत: बीमा कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस, मृतक के वारिसों को क्षतिपूर्ति के तौर पर 1.65 करोड़ रुपए याचिका दायर करने की तारीख से 6 प्रतिशत ब्याज सहित दे। अदालत ने यह आदेश इंदू डंगायच व अन्य की क्लेम याचिका पर दिए। क्लेम याचिका में कहा गया कि 8 मार्च 2020 को याचिकाकर्ता के पति योगेन्द्र ढंगायच विपक्षी बीमा कंपनी से बीमित बस के जरिए अहमदाबाद से जयपुर आ रहे थे। शाम करीब 7.30 बजे अजमेर के आदर्श नगर थाना इलाके में बस चालक ने तेज गति व लापरवाही से वाहन को डिवाइडर से टकरा दिया। जिससे बस अनियंत्रित होकर पलट गई और उसमें बैठे योगेन्द्र की मौत हो गई। यह दुर्घटना बस चालक की लापरवाही व तेज गति से वाहन चलाने से कारण हुई। इसलिए उन्हें बीमा कंपनी व अन्य से क्लेम राशि दिलवाई जाए। जवाब में बीमा कंपनी ने कहा कि दुर्घटना चालक की लापरवाही से नहीं हुई। चलती बस का टायर फट गया था और यह घटना एक्ट ऑफ गॉड है। इसलिए क्लेम याचिका खारिज की जाए।

मोहन भागवत ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आर.एस.एस. के कार्यक्रमों एवं समारोहों में भाग लेने पर लगी हुई थी। लगता है कि मेल-मिलाप एवं समझौतावादी इन प्रयासों के बावजूद, आर.एस.एस. एवं भाजपा के बीच का अविश्वास कम हुआ प्रतीत नहीं हुआ है।

उल्लेखनीय है कि केरल में आयोजित त्रिदिवसीय बैठक की शुरुआत से एक दिन पूर्व, मुम्बई में आयोजित "फिनटेक ग्लोबल समिट" में प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने चौथे कार्यकाल की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि वे "2029 में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन के 10वें संस्करण में भी यहाँ होंगे।" संसद में स्पष्ट बहुमत लाने में भाजपा के असफल रहने के बाद, इस प्रकार की अफवाहें जोरों पर हैं कि आर.एस.एस. तथा भाजपा के अंदर मौजूद प्रधानमंत्री पद आकांक्षी नेताओं ने भी पार्टी को आगे ले जाने के लिये मोदी से परे देखना शुरु कर दिया है। मोदी की सोच के अनुसार, पहली और दूसरी बार ही नहीं बल्कि तीसरी बार भी जनादेश उनके लिये मिला था, भाजपा के लिये नहीं।

जाहिर है, मोहन भागवत इस बात से असहमत हैं तथा बार-बार चेतावनी के संकेत दे रहे हैं।

उन्होंने एक बार फिर पुणे में बड़ा गूढ़ बयान दिया। उन्होंने कहा कि, "कुछ लोग सोचते हैं कि शान्त-अशान्त रहने के बजाय, हमें आकाशीय बिजली की तरह चमकना चाहिये। लेकिन जब बिजली चमकती है, उसके बाद अँधेरा पहले से भी ज्यादा गहरा हो जाता है। इसलिये, कार्यकर्ताओं को दीपकों की तरह जलना चाहिये तथा आवश्यक हो जाने पर ही चमकना चाहिये।"

विनेश...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उस वक्त यदि यह बात स्पष्ट नहीं थी, तो अब पूरी तरह स्पष्ट है।"

कांग्रेस को उम्मीद है कि - इन दोनों पहलवानों के पार्टी में आने से आगामी चुनावों में जाट वोटर्स में पार्टी की संभावनाएं बेहतर बनेंगी, साथ ही इससे राजस्थान, दिल्ली और उत्तरप्रदेश के जाट बहुल क्षेत्रों में सकारात्मक संदेश जाएगा।

पिछले माह, अधिक वजन के कारण जब विनेश फोगाट ओलंपिक मैडल हासिल करने से वंचित रह गई थीं, तब भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने उन्हें राज्यसभा सीट देने का प्रस्ताव दिया था।

'सूचना प्रौद्योगिकी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

शर्मा की रिविजन याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालती आदेश की पालना में ए.सी.बी. के डी.जी. रवि मेहरडा अदालत में हाजिर हुए। अदालत ने उनसे पूछा कि आपके विभाग ने मामले में एफ.आर. कैसे लगा दी, लेकिन डी.जी. ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर अदालत ने उनसे कहा कि सही दिशा तो यह होती कि आप टैंडरों की जांच करते कि किसे कितना पैसा मिला व किसे टैंडर मिला। दूसरी तरफ, याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि ए.सी.बी. ने गलत तौर पर एफ.आर. लगाई है, डी.ओ.आई.टी. में बहुत भ्रष्टाचार है। अदालत ने ए.सी.बी. के डी.जी. को मौखिक रूप से कहा कि वे विभाग के पिछले पांच साल के सभी टैंडरों की जांच करें और इसकी रिपोर्ट चार सप्ताह में कोर्ट में पेश करें। ए.सी.बी. डीजी ने अदालत से कहा, टैंडरों की संख्या अधिक होने के कारण जांच पूरी करने के लिए अधिक समय दिया जाए, लेकिन अदालत ने इससे मना करते हुए कहा कि जांच शुरू होने के बाद यदि समय कम रहा तो उसे बाद में देखेंगे। याचिका में वर्ष 2019 में डी.ओ.आई. टी. विभाग के तत्कालीन उपनिदेशक कुलदीप यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में ए.सी.बी. की ओर से एफ.आर. लगाने को चुनौती दी गई है।

'असंगठित और निजी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बल्कि, यह एक महिला की पहचान और उसकी गरिमा का मौलिक पहलू है। अदालत ने कहा कि किसी महिला कर्मचारी को मातृत्व अवकाश देने में सिर्फ इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता कि वह आर.एस.आर.टी.सी. में काम कर रही है। मातृत्व अवकाश को लेकर वर्ष 2017 में संशोधन कर इसे 180 दिन का किया गया है। ऐसे में रोडवेज़ वर्ष 1965 के विनियम का सहारा लेकर सिर्फ 90 दिन का अवकाश नहीं दे सकता। याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता रोडवेज़ में कंडक्टर पद पर कार्यरत है। उसने संतान को जन्म देने के बाद 180 दिन का मातृत्व अवकाश लेने के लिए आवेदन किया, लेकिन उसे 90 दिन का अवकाश ही दिया गया। इसलिए उसे 90 दिन का अवकाश और दिलाया जाए। इसका विरोध करते हुए रोडवेज़ की ओर से कहा गया कि वर्ष 1965 के विनियम के नियम 74 के तहत 90 दिन का ही मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है, इसलिए याचिका को खारिज किया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने केन्द्र और राज्य सरकार को असंगठित और निजी क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को 180 दिन का अवकाश देने के संबंध में निर्देश देने और रोडवेज़ को याचिकाकर्ता को इसका लाभ देने को कहा है।

भारत ने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बाद किया गया है। इससे पहले 6 जून 2022 में इसका परीक्षण किया गया था। ये मिसाइल मारक क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

'सदा सूखाग्रस्त रहने वाले देश के 45 प्रतिशत जिले बाढ़ की चपेट में'

जलवायु परिवर्तन की अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, यह पिछली एक सदी में वायुमंडल के तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का परिणाम है

नयी दिल्ली, 6 सितंबर (वार्ता)। जलवायु परिवर्तन भारत में 85 प्रतिशत से अधिक जिले चक्रवात, बाढ़, सूखे और गर्मी के संकट से प्रभावित रहते हैं और जलवायु परिवर्तन से ऐसी प्राकृतिक आपदायें अधिक विनाशकारी होती जा रही हैं। यह बात आईपीई ग्लोबल और एसरी-इंडिया की शुक्रवार को जारी एकअध्ययन रिपोर्ट में कही गयी है।

अध्ययन में यह भी पाया गया है कि देश के 45 प्रतिशत जिले जो कभी सूखा-प्रवण होते थे, वहां बाढ़ का प्रकोप दिखने लगा है , इसी तरह जहां पहले बाढ़ की प्रवणता थी वहां सूखे के प्रकोप ने स्थान लेना शुरू कर दिया है। आईपीई ग्लोबल में जलवायु परिवर्तन और स्थिरता संबंधी कार्य-प्रभाग के प्रमुख और इस अध्ययन रिपोर्ट के लेखक अविनाश मोहंती ने कहा, " देश में हर 10 में से नौ लोग आज जलवायु संबंधी विनाशकारी घटनओं के जोखिम में हैं, यह पिछली एक सदी में वायुमंडल के तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का परिणाम है।

रिपोर्ट के अनुसार प्राकृतिक घटनाओं की तीव्रता आवृत्ति, और इनके अप्रत्याशित रूप से घटित होने की प्रवृत्तियां चार गुना बढ़ गई हैं। इस अध्ययन में वर्ष 1973 से 2023 तक के 50 साल के कालखंड में चरम जलवायु घटनाओं की एक सूची संकलित कर करके उनकी जटिलताओं और परिवर्तनशील रुझानों और स्वरूपों की खोज करते हुये एक विस्तृत जिला-स्तरीय मूल्यांकन किया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले दशक में ही इन जलवायु चरम सीमाओं में पांच गुना वृद्धि देखी गई है। अध्ययन में यह भी पाया गया है कि भारतीय जिलों का समग्र जलवायु जोखिम परिदृश्य तेजी से बदल रहा है।

इस अध्ययन को ईएसआरआई-इंडिया और उसके सहयोगी आईपीई ग्लोबल द्वारा आयोजित जलवायु प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र में जारी किया किया गया।

रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से देश की कृषि और उद्योगों तथा अवसंरचना को जलवायु परिवर्तन की अनिश्चितताओं से बचान के लिए अधिक विवरणात्मक जोखिम-आकलन को अपनाने और जलवायु-जोखिम वेधशालायें और अवसंरचना जलवायु कोष स्थापित करने की सिफारिशें की गयी हैं।

रिपोर्ट के अनुसार बिहार, आंध्र प्रदेश, ओडिशा गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और असम के 60 प्रतिशत से अधिक जिले एक से अधिक चरम जलवायु घटनाओं का सामना कर रहे हैं। आईपीई ग्लोबल अध्ययन में पाया गया कि पूर्वी क्षेत्र के जिले अत्यधिक बाढ़ की घटनाओं के लिए अधिक प्रवण हैं, इसके बाद भारत के उत्तर-पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र हैं। इन जिलों में अत्यधिक बाढ़ की घटनाओं में 4 गुना वृद्धि हुई है।

एसरी इंडिया के प्रबंध निदेशक, अगेंद्र कुमार ने कहा, नीतिगत हस्तक्षेपों के लिए भविष्य के जलवायु के अनुमानों को समझना हो या इनके संबंध में प्रकृति-आधारित समाधान, तकनीकी समाधान या सामाजिक समाधान जैसे हस्तक्षेप के लिये कुशलतापूर्वक योजना बनाना, भौगोलिक सूचनायें महत्वपूर्ण हैं।

'सेबी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किया है कि संसद द्वारा कानूनन निर्मित नियामक इकाइयों की जांच की जाए। पी.ए.सी. के प्रमुख के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि कमेटी बुच को पूछताछ के लिए बुलाने पर विचार कर रही है।

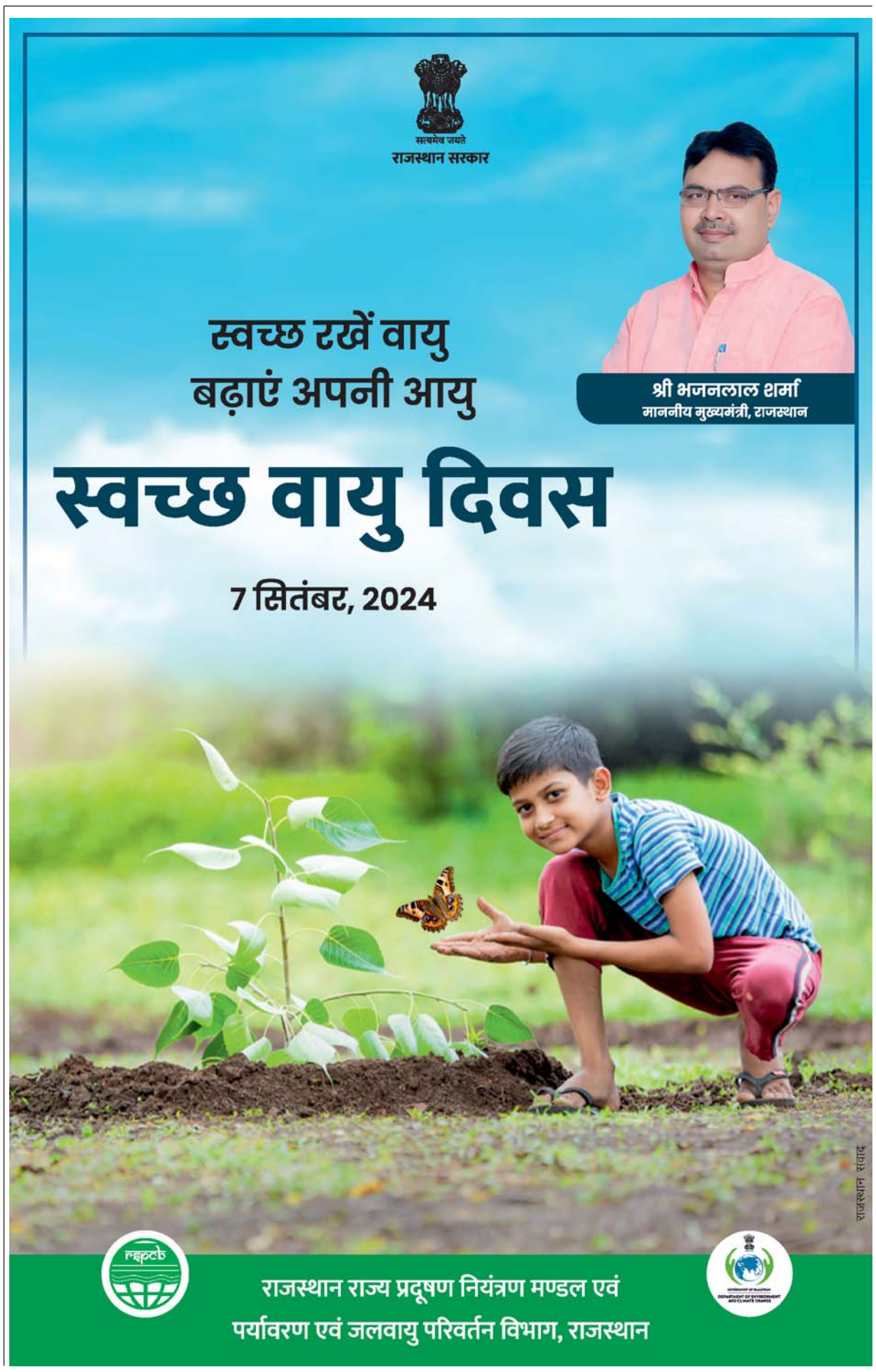

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908